सी. के. प्रहलादा और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 3325/2008)

6 मई, 2008

[एस. बी. सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136-विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र-अपने भाई की मृत्यु पर अपीलार्थी के पिता के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का प्रयोग-अपीलार्थी के पिता द्वारा मुकदमा जिसमें अस्पताल के अधिकारियों को भाई के शरीर से हटाई गई वस्तुओं को उन्हें सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई है-आदेश दिया गया-6 साल के बाद निष्पादन याचिका-राज्य द्वारा अपील-2487 दिनों की देरी को माफ करने के लिए भी आवेदन-उच्च निचली अदालत द्वारा अनुमत अपील के रूप में आवेदन और निचली अदालत को प्रेषित मामला-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःउत्तराधिकार प्रमाण पत्र सीमित उद्देश्य के लिए दिया जाता है-इसे प्राप्त करने से व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता है-उच्च न्यायालय ने मुकदमा से कहा कि मृतक की पत्नी एक आवश्यक पक्ष थी-उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने के लिए कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान उसकी मृत्यु पर, उसके उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकारों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था-इससे भी अधिक, अपील दायर करने में देरी को माफ नहीं किया जाता था-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पहली अपील की अनुमति दी-इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए-मृतक के गोद लिए गए बेटे को मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

अपीलार्थी के चाचा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपीलार्थी के पिता ने अपने भाई के शरीर से सभी वस्तुओं को हटा दिया। अपीलार्थी के चाचा की मृत्यु हो

गई। अस्पताल के अधीक्षक ने अपीलार्थी के पिता से आग्रह किया कि वे मृत शरीर को सौंपने से पहले उनके द्वारा रखी गई वस्तुओं को वितरित करें ताकि उन्हें इसके लिए हकदार व्यक्तियों को वितरित किया जा सके। ये सामान अस्पताल के अधिकारियों को सौंप दिए गए। इसके बाद, अपीलार्थी के पिता ने अधिकारियों से लेख मांगे।हालाँकि, अस्पताल के अधिकारियों ने अपीलार्थी के पिता को वस्तुओं की वापसी के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा। अपीलार्थी के पिता ने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया।मृतक की जी-पत्नी को एक पार्टी के रूप में शामिल किया गया था। जी की कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान मृत्यु हो गई, और वे अपने पीछे एस-हेर गोद लिए हुए बेटे को छोड़ गए। अपीलार्थी के पिता को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिया गया था। हालांकि, उसी के उत्पादन पर, अस्पताल के अधिकारियों ने सामान वापस नहीं किया।अपीलार्थी के पिता ने एक मुकदमा दायर कर अस्पताल के अधिकारियों को अपीलार्थी को सामान सौंपने का निर्देश देने की मांग की।धारा 80 ({2) सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और इसकी अनुमति दी गई थी।मुकदमा था

एकपक्षीय फैसला किया गया। छह साल बाद फांसी का मामला दर्ज किया गया। सम्मन देना की प्राप्ति पर, राज्य ने अपील दायर की। इसने देरी को माफ करने के लिए भी आवेदन दायर किया और इसकी अनुमति दी गई। उच्च निचली अदालत ने माना कि निचली अदालत द्वारा पारित आदेश टिकाऊ नहीं था और मामले को निचली अदालत को भेज दिया। इसलिए वर्तमान अपील याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक सीमित उद्देश्य के लिए दिया जाता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला न्यायालय अधिकार के सवाल का फैसला नहीं करता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के एक नामांकित व्यक्ति या धारक का कर्तव्य है कि वह संपत्ति को उस व्यक्ति को सौंप दे जिसका कानूनी अधिकार है। केवल

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने से, कोई व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता है।[पैरा 10] [858-डी-ई]

विद्याधबरी और अन्य बनाम सुखराना बाई और अन्य 2008 (2) एस. सी. सी. 238-निर्दिष्ट।

1.2 चोर न्यायालय अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करना विधिसम्मत है। इस न्यायालय के पास ऐसा करने के लिए आवश्यक पक्षकारों को पूर्ण न्यायाधीश आदेश पारित करने की शक्ति है।उच्च न्यायालय ने उचित रूप से माना कि यह एक आवश्यक पक्ष था। चूंकि कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को उक्त कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था। हो सकता है कि यह फरमान एकपक्षीय पारित किया गया हो, लेकिन जब इसे न्यायालय की सूचना लाया गया हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 10] [858-ए-सी]

एम/एस. तन्ना और मोदी बनाम सी.आई.टी. मुंबई XXV और अन्य। 2007 (8) स्केल 511-पर निर्भर था।

1.3 अपील दायर करने में भारी देरी हुईः आम तौर पर, यह न्यायालय अपील दायर करने में उक्त देरी को माफ नहीं करता, लेकिन तत्काल मामले में, राज्य द्वारा दायर पहली अपील को भी उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.10.2005 के फैसले में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, जिसका प्रभाव इसके दिनांकित 1.12.2005 के आदेश को भी रद्द करने का होगा।तथापि, राज्य को अपीलकर्ता को लागत के रूप में Rs.10,000/- की राशि का

भुगतान करना होगा। यह आगे निर्देश दिया जाता है कि बी को मुकदमे में एक मुकदमा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता मुक़दमे में इस तरह की अन्य राहत या राहत के मुकदमा प्रार्थना करने के मुकदमा खुला होगा।[पैरा 12] [859-बी-ई]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णयः2008 दीवानी याचिका सं 3325।

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के आर एफ ए सं 1283/2004 के निर्णय और आदेश दिनांक 1.12.2005 से पारित

अपीलार्थियों की ओर से किरण सूरी, अपर्णा भट और एस. जे. अमित।

प्रतिवादीओं के लिए संजय आर. हेगड़े।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अवकाश अनुदत्त की गई।

2. यह अपील बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.10.2005 और दिनांक 1.12.2005 के आदेशों के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत अपील दायर करने में 2487 दिनों की देरी को माफ कर दिया गया है और उक्त अपील को अनुमति दी गई है।

3. इस मामले का मूल तथ्य विवाद में नहीं है।अपीलकर्ता के पिता, मदवरमनाचर के भाई को बैंगलोर के एस. डी. एस. टी. बी. अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपीलकर्ता के पिता ने उसके भाई के शरीर से सभी वस्तुओं को हटा दिया था। उसकी मृत्यु के बाद, अपीलकर्ता के पिता ने अस्पताल के अधिकारियों से जब्त की गई वस्तुओं को सौंपने का अनुरोध किया, जिसके लिए 9.6.1981 पर एक लिखित अनुरोध किया गया था।

उक्त अस्पताल के अधीक्षक ने एक आदेश पारित किया कि अपीलार्थियों के पिता द्वारा रखी गई वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए अस्पताल के अधिकारियों को वापस दिया जाना चाहिए ताकि वे उन्हें इसके लिए हकदार व्यक्तियों को वितरित कर सकें। शव को सौंपने से पहले आर्टिज की डिलीवरी पर जोर दिया गया था। उक्त वस्तुओं को अस्पताल के अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिसके लिए एक पावती जारी की गई।

4. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक आवेदन अपीलार्थियों के पिता द्वारा 24.8.1981 पर दायर किया गया था। उक्त कार्यवाही में मृतक की पत्नी गौरम्मा को एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। उक्त कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वह कथित तौर पर एस. बासवराजप्पा के पीछे रहती है, जिसे उसका गोद लिया हुआ बेटा कहा जाता है। दिनांक 5.7.1991 के एक आदेश द्वारा, निम्नलिखित के संबंध में अपीलकर्ता के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया थाः

1.	विजय बैंक तोगरसी में राशि एस. बी. खाता सं 309 ब्याज	रू.5-00
2.	सिंडिकेट बैंक में राशि,शिमोगा एस. बी. खाता सं.27717 लेजर फोलियो सं.30 ब्याज	रू.318-65
3.	सिंडिकेट बैंक में राशि,शिमोगा कोप्पा, एस. बी. खाता सं.7/89 फोलियो 4289/17 ब्याज	रू.19379-59

बैंगलोर के अस्पताल में जमा किए गए मृतक के सोने के सामान।

	ग्राम	मि. ग्रा.
एक सुदर्शन रिंग	11	700

लाल पत्थरों वाली एक अंगूठी	5	300
एक फिनब शिगड पत्थर गाता है।	6	600
एक बार	46	800
	39	450
नकद	160	00

5. उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के उत्पादन के बावजूद अस्पताल के अधिकारियों ने अपीलकर्ता के पिता को उक्त वस्तुओं और दस्तावेजों को वापस नहीं किया, जबकि अतिरिक्त शहर सिविल न्यायाधीश, बैंगलोर की अदालत में एक मुकदमे में अस्पताल के अधिकारियों-प्रतिमुकदमाियों को अपीलकर्ताओं को वस्तुओं को सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई थी या वैकल्पिक रूप से उस मूल्य का भुगतान किया गया था जिसका मूल्यांकन Rs.45,000/- पर किया गया था। हालाँकि, सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 80 के तहत राज्य को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। संहिता की खंड 80 की उप-खंड (2) के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसकी अनुमति दी गई है।

विद्वत विचारण न्यायाधीश के समक्ष, राज्य द्वारा कोई स्पष्ट बयान दायर नहीं किया गया था। यह आदेश दिया गया था कि 31.10.1997 एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था,

7. वर्ष 2003 में उक्त डिक्री के निष्पादन के लिए एक निष्पादन मामला दायर किया गया था। निष्पादन न्यायालय द्वारा उपनामकों की प्राप्ति पर, कर्नाटक राज्य द्वारा पहली अपील की गई थी। जैसा कि यहाँ पहले संकेत दिया गया था, इसे 2487 दिनों के लिए प्रतिबंधित किया गया था।

2005 की आइए संख्या 1 के रूप में उक्त अपील में देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे दिनांक 24.10.2005 के फैसले के कारण अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 1.12.2005 के निर्णय के कारण उक्त डिक्री में विभिन्न कमियों की ओर इशारा किया और राय दी कि विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री कानून में टिकाऊ नहीं थी।

बयान करते हुएः

(i) सिविल संहिता की खंड 80 की उप-खंड (2) के संदर्भ में मुकदमा दायर करने के लिए कोई तात्कालिकता नहीं दिखाई गई थी।

प्रक्रिया;

(ii) श्रीमती गौरम्मा मुक़दमे में एक आवश्यक पक्षकार थींःऔर

(ii) उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में वस्तुओं के मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया था। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि अभियोक्ता मृतक का एकमात्र उत्तराधिकारी था। इसका निर्देशन किया गया थाः

> "अपील को 0 में किए गए विवादित निर्णय और डिक्री दिनांक 31.10.1997 की अनुमति दी जाती है।एस. बैंगलोर शहर में अतिरिक्त सिटी सिविल जज की फाइल पर एस. No.3830/1994 को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को बिना किसी सूचना के 23.12.2005 पर आगे की कार्यवाही के लिए निचली अदालत के समक्ष पेश होने के निर्देश के साथ निचली अदालत को वापस भेज दिया जाता है।
>
> इसके अलावा, निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिमुकदमाियों को 23.12.205 से 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दायर करने और कानून के अनुसार मुकदमे का निपटारा करने का अवसर प्रदान करे।"

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री किरण सूरी प्रस्तुत करेंगी कि उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा अपील को प्राथमिकता देने में 2487 दिनों की देरी को माफ करने में गंभीर त्रुटि की है। इसके अलावा यह भी आग्रह किया गया कि अपीलकर्ता किसी भी कारण को साबित करने में विफल रहा है, इसके लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च निचली अदालत को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले को निचली अदालत को वापस नहीं भेजना चाहिए था कि उसके विचार के लिए जो छोटा सवाल उठा था वह यह था कि क्या अस्पताल के अधिकारी हैं।

अपीलार्थियों के पिता से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहने के बाद, वे उसे प्रस्तुत करने पर उसे सामान वापस करने के लिए बाध्य थे।

9. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हेगड़े ने हालांकि विवादित फैसले का समर्थन किया।

10. एक गौरम्मा, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने की कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था।उसने खुद को मृतक की पत्नी होने का दावा किया। अपीलकर्ता को पता था कि अस्पताल के अधिकारियों ने उसे दस्तावेज़ और सामान सौंप दिए थे।इसलिए, वह एक आवश्यक पार्टी थीं।चूंकि कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को उक्त कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था।

हो सकता है कि डिक्री एकपक्षीय पारित की गई हो, लेकिन जब इसे इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है, तो हमारी राय में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

अब यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि यह न्यायालय अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करना विधिसम्मत है।(मेसर्स तन्ना और मोदी अन्य सी. एल. टी. मुंबई एक्स. एक्स. वी. और अन्य देखें। [2007 (8) स्केल 511] इस न्यायाधीशालय के पास पक्षों के साथ पूर्ण न्यायाधीश करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति है।उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में, सही निर्णय दिया है कि उपरोक्त स्थिति में, गौरम्मा एक आवश्यक पक्ष थी।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक सीमित उद्देश्य के लिए दिया जाता है।उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला न्यायालय अधिकार के सवाल का फैसला नहीं करता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के एक नामांकित व्यक्ति या धारक का कर्तव्य है कि वह संपत्ति को उस व्यक्ति को सौंप दे जिसका कानूनी अधिकार है। केवल उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने से, कोई व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता है।

11. विद्याधारी और अन्य. वी. मेंसुखराना बाई अन्य अन्य। [(2008) 2 एस. सी. सी. 238], इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

> "14, इसलिए, हालांकि हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि सुखराना बाई अभी तक एकमात्र वैध पत्नी थीं, हम विद्याद * के पक्ष में प्रमाण पत्र देने का विकल्प चुनेंगे जो उनके मनोनीत और उनके चार बच्चों की माँ थीं। हालाँकि, हमें इक्विटी को संतुलित करना चाहिए क्योंकि सुखराना बाई भी कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक हैं और चार बच्चों के अलावा शीतलदीन की संपत्ति में उनकी बराबर हिस्सेदारी होगी जो 1/5 होगी।इक्विटी को संतुलित करने के लिए, हम विद्याधारी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने का विकल्प चुनेंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह शीतलदीन की संपत्तियों में सुखराना बाई के 1/5 "हिस्से

की रक्षा करेगी और उसे सौंप देगी।नामांकित व्यक्ति के रूप में वह ट्रस्ट में सुखराना बाई का 1/5 "हिस्सा रखेंगी और सुखराना बाई को उसी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगी। हम निर्देश देते हैं कि इस उद्देश्य के लिए वह निचली निचली अदालत को संतुष्ट करने के लिए निचली निचली अदालत में सुरक्षा प्रदान करेगी।" (जोर दिया गया)

12. यह सच हो सकता है कि अपील दायर करने में भारी देरी हुई थी। आम तौर पर, यह न्यायालय अपील दायर करने में उक्त देरी को माफ नहीं करता, लेकिन इस मामले में, राज्य द्वारा दायर पहली अपील को भी उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां हमें उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.10.2005 के फैसले में हस्तक्षेप करना चाहिए, जिसका प्रभाव इसके दिनांकित 1.12.2005 के आदेश को भी रद्द करने का होगा। लेकिन हमारा मानना है कि राज्य को अपीलकर्ता को लागत के रूप में Rs.10,000/- की राशि का भुगतान करना होगा। हम आगे निर्देश देते हैं कि बासवराजप्पा को मुकदमा में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता के मुकदमा यह भी खुला रहेगा कि वह मुकदमे में ऐसी अन्य राहत या राहत के मुकदमा प्रार्थना करे जो उसे मामले में सलाह दी जा सकती है।

13. अपील को उपरोक्त निर्देशों के साथ खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एन. जे. याचिका खारिज कर दी गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास' की सहायता से** अनुवादक द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।